

ਮोदी 3.0 की मजबूती को लेकर अलग-अलग चर्चाओं के दौर

हालांकि इस पर सफाई भी आई। लोकन यह भी सहा है कि इस बार सभ विद्या साक्षय नहीं दिख जैसे पहले के चुनावों में दिखता था वहीं प्रधानमंत्री का एनडीए का 400 पार और भाजपा खुद 370 जीतने का नाश लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया। अब सबकी निगाहें लोकसभा अध्यक्ष पर हैं जिस पर फिर क्यासों का दौर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से विविधताओं से भरे भारत देश और उसकी राजनीति में मतांतर नए नहीं है। इसीलिए कभी लगता है कि मोदी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बेहद मजबूत है तो कभी लगता है कि भाजपा और उसके अपने महत्वपूर्ण आनुषांगिक दल ही क्यों खफा हैं। आंध प्रदेश विधानसभा में गजब का प्रदर्शन करते हुए टीडीपी-भाजपा गठबंधन ने बड़े बहुमत वाली जीत हासिल की। दोनों का एजेंडा सबको पता है। टीडीपी मुख्लिग आरक्षण, परिसीमन, सी.ए.ए., अमरावती के विकास और विशेष दर्जे पर तबज्जो चाहेगी तो कमोवेश जेडीयू भी बिहार में ऐसे ही एजेंडे के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव में जाएगी।



ऋतुपण दव
लेखक

मा

ना दी मत्रिमण्डल का गठन जरूर हो गया है लेकिन कायासों का दौर खत्म नहीं हुआ। एक बार में ही 72 सदस्यीय भारी भरकम मत्रिमण्डल की वजहे लोग कुछ भी बताएं लेकिन यह नरेन्द्र मोदी की चतुराई कही जाएगी जो उन्होंने एक बारगी सारे किन्तु-परन्तु पर विराम लगा एक तीर से कई निशान साधे। इससे न के बल अब भारी भरकम के आनुषांगिक संगठनों को भी बड़ा संदेश गया कि भले ही सीटें घटीं लेकिन मोदी की हैसियत वही है। घटक दलों के सहयोगियों को मोदी के तीसरे कार्यकाल में मत्रिमण्डल बंटवारे में मिले पढ़ और कदसे भी काफी भ्रमटूटा साफ दिखा कि नरेन्द्र मोदी ने जो चाहा वो किया जिस शांति और धैर्य से घटक दलों के साथ पहली बैठक हुई, प्रमुख दोनों सहयोगी नीतिशब्द और चंद्रबाबू ने मोदी की तारीफ में कसरी पढ़े। उससे राजनीतिक नब्ज टटोले वालों की भी धड़कनें असहज हुईं। हम उम्र और राजनीति में मोदी से सीनियर होने के बावजूद नीतिश का उनके पैर छूने ज़क्कना सबको अब भी हैरान कर रहा है। यह भ्रम ही साबित हुआ कि जेडीयू को रेल तो नीडीपी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिलना तय है तुरुणी सरकारे में रेल मंत्रालय प्रयोग: गठबन्धन के सहयोगियों के खाते में रहा मौजूदा मत्रिमण्डल में 33 नए चेहरे हैं जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पहली बार मंत्री बनने वाले में सहयोगी दलों से हैं। 17 महिलाएं भी मंत्री बनीं जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं एक भी मुस्लिम मत्रिमण्डल में नहीं है। आजादी के बाद पहला भौक है जब मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। नए मत्रिमण्डल में 21 सर्वर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों को जगह मिली। भावुक अपीलों और जनता से कनेक्ट होने में हुनरमंद मोदी का कोई सानी नहीं। अब उन्होंने नई अपील कर विषय को बहस का नया मुद्दा दे दिया। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से मोदी का परिवार हटाने की गुहारलगा दी। भले ही डिस्प्ले नाम बदलेलेकिन भारत की तरकी की कोशिशों के खातिर प्रयास करने वाले एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट है। इशारा अबकी बार एनडीए सरकार की ओर तो था ही साथ ही गठबन्धन के सहयोगियों को भी बता दिया कि अब वो कितने अहम हैं? इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को देखना होगा जिसमें उन्होंने मणिपुर में शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त जताई और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसा नागपुर में आरएसएस प्रशिक्षुओं को मोहन भागवत ने कहा कि 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी। लेकिन साल भर संएकाएक हिंसा बढ़ गई। इसपर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मणिपुर साल भर से शांति की राह देख रहा है। अब सरकार भी बन गई तब भी चर्चा नहीं रुकी कि जो हुआ वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? झूठ भा कायदे से पेश किया गया। ऐसे में देश कैसे चलेगा? विषय को विरोधी नहीं मानना चाहिए। उसकी राय जरूरी है। चुनावी गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया जो जरूरी है। अभी चुनावियां खत्म नहीं हुई हैं। यह बयान शायद भाजपा प्रमुख नड्डा के उस बयान का जवाब लगता है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा अब अपने पैरों पर खड़ी है। भागवत के बाद संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार का बयान भी सुर्खियों में रहा जिसमें उन्होंने भी भाजपा की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा। हालांकि इस पर सफाई भी आई। लेकिन यह भी सही है कि इस बार संघ वैसा सक्रिय नहीं दिखा जैसे पहले के चुनावों में दिखता था वहाँ अधिकारी विधायिका का एनडीए का 400 पर और भाजपा खुद 370 जीतने का नारा लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया। अब सबकी निगाहें लोकसभा अध्यक्ष पर है। जिस पर फिर कायासों का दौर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से विविधताओं से भरे भारत देश और उसकी राजनीति में मतातंत्र नए नहीं है। इसीलिए कभी लगता है कि मोदी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बेहद मजबूत है तो कभी लगता है कि भाजपा और उसके अपने महत्वपूर्ण आनुषांगिक दल ही क्यों खफा हैं। अंध्र प्रदेश विधानसभा में जगब का प्रदर्शन करते हुए टीडीपी-भाजपा गठबन्धन ने बड़े बहुमत वाली जीत हासिल की। दोनों का एजेण्डा सबको पता है। टीडीपी मुस्लिम आरक्षण, परिसीमन, सी.ए.ए., अमरावती के विकास और विशेष दर्जे पर तबज्जो चाहेगी तो कमोवेश जेडीयू भी बिहार में ऐसे ही एजेण्डे के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव में जाएगी। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव होने हैं। इन हालातों में महत्वपूर्ण घटक कब तक भाजपा के हमराह रहेंगे? जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित बिहार में पढ़ और कद पर कई बातें होनी शुरू हो गई हैं। अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम भाजपा नीत गठबन्धन सरकार को लेकर दुनिया भर में कौतूहल था। लेकिन मत्रिमण्डल गठन के बाद विभाग वितरण से लोग भौंचक्का हैं कि यह कैसा जादू? क्या सचमुच राजनीति में मंजे दोनों बाबू न के बल मोदी के साथ हैं बल्कि ब्रांड मोदी के दो हाथ हैं? बहुमत का आंकड़ा न छूपने के बावजूद मत्रिमण्डल बंटवारे में दिखी मोदी के मन की बात ने क्या सभी का लोहा मनवा लिया? हालांकि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतिश का न जाना फिर चचार्हों में है। लेकिन इटली में जी-7 सम्मेलन में बिना सदस्य रह कर और दुनिया के प्रधानमंत्री को बुलाना और दुनिया के शीर्ष नेताओं से मेल-मुलाकात के बाद मोदी की नई छवि और कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक चचार्हों ने नया मोड़ जरूर ले लिया है। लेकिन देश के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और दक्षिण के चुनाव परिणामों के मायने पर भी जानकारों की राय बंटी हो सकती है। लेकिन यह सच है कि असल परीक्षा के लिए लोकसभा के नियमित सत्र और नए अध्यक्ष तक इंतजार करना ही होगा। नई परिस्थितियों में खुद की छवि को बजाए मसीहाई दिखाने के बड़ी सहजता और विनम्रता से लबरेज दिखाकर भी प्रधानमंत्री मोदी नई एनडीए सरकार के वैसे ही सख्त मुखिया दिख रहे हैं जैसे बीते दोनों कार्यकाल में रहे लोग तब और अब भी भले हूँदें लेकिन यह कब दिखेगा, कोई नहीं जानता। फिलाहाल 30 जून का इंतजार है जब मन की बात के जरिए तीसरे कार्यकाल में नरेन्द्र मोदी का पहला संबोधन क्या होगा?

भारत में लागक असमानता का बढ़ता खाइ



लालत गग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

Tq

ख आयक मध्य द्वारा हाल मध्य प्रस्तुत किये गए लैंगिक अंतर के अंकड़ों ने एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा किया है कि शिक्षा, आय, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आधी दुनिया को उसका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? निसर्सदै, हमारे सताधीशों को सोचना चाहिए कि लैंगिक सूचकांक में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर क्यों है? लगातार महिलाओं की दोयम दर्जा की स्थिति का बना रहना नीति-नियंताओं के लिये आत्ममंथन का मौका है। निश्चय ही यह स्थिति भारत की तरकीकी के दावों से मेल नहीं खाती। इसके बावजूद उम्मीद जगाने वाला तथ्य है कि पिछले वर्ष जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं की एक तिहाई हिस्सेदारी को लेकर विधेयक परित हो चुका है। इसके बावजूद हाल में सामने आए अंकड़े परेशन करने वाले हैं और तरकीकी के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। यह विचारणीय प्रश्न है कि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाने और कायदे कानूनों में बदलाव के बावजूद लैंगिक असमानता की खाई गहरी क्यों होती जा रही है? ये स्थितियां समाज में इस मुद्दे पर खुले विवरण की तरफ से नहीं की जा सकती। इसमें दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में सरकारों द्वारा लागक समानता के लिये नातया बनाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं। जिसकी एक वजह समाज में पुरुष प्रधानता के सोच भी है। जिसके चलते यह आधार होता है कि आधी दुनिया के कल्याण के लिये बनी योजनाएं महज घोषणाओं तथा फाइलों तक सिमट कर रह जाती हैं। भारत में महिलाओं की उपेक्षा, भेदभाव, अत्याचार एवं असमानता की स्थितियों का बना रहना विडम्बनापूर्ण है। भारत में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के स्वर तो बहुत सुनने को मिलते हैं, महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार भी पुरुषों के बराबर दिया गया है, परन्तु यदि वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक एवं विसंगतिपूर्ण है। हमारे सताधीशों के लिये यह तथ्य विचारणीय है कि हमारे समाज में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है? हम समान कार्य के बदले महिलाओं को समान बैतन दे पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जाहिर है यह अंतर तभी खत्म होगा जब समाज में महिलाओं से भेदभाव की सोच पर विराम लगेगा। यह संतोषजनक है कि द्वितीया में नामांकन में लाइक समानता की स्थिति सुधरी है। फिर भी महिला सशक्तीकरण की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देर-सर्वर महिला आरक्षण कानून का ईमानदार क्रियान्वयन समाज में बदलावकारी भूमिका निभा सकता है। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक नेतृत्व इस मुद्दे को अपेक्षित गंभीरता के साथ देखे। महिलाएं ही समस्त मानव प्रजाति की धूरी हैं। वो न केवल बच्चे को केसशक्तिकरण का सबसे बड़ा मन्दिरी हैं बल्कि उनका भरण-पोषण और उन्हें संस्कार भी देती हैं। महिलाएं अपने जीवन में एक साथ कई भूमिकाएं जैसे- मां, पती, बहन, शिक्षक, दोस्त बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाती हैं। बावजूद क्या कारण है कि आज भी महिला असमानता की स्थितियां बनी हुई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए भारत सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे। सरकार को अपनी लैंगिकवादी सोच को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार के खुद के कर्मचारियों में केवल 11 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये अधिक एवं नवे अवसर सामने आने जरूरी है। भारत में महिलाओं से भेदभाव की सोच पर विराम लगेगा। यह संतोषजनक है कि द्वितीया का सबसे मुश्किल कामों को करता है। अब हम वह कह सकते हैं कि वर्स संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा पेशा है, जिसमें 24 घंटे, सातों दिन आप काम पर रहते हैं, हर रोज क्राइसिस ज्वेलरी है, हर डेटलाइन को पूरा करते हैं और वह भी बिना छुट्टी के। सोचिए, इतने सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही उसके द्वारा काम को राष्ट्र की उन्नति में योगभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। प्रश्न है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का अर्थिक मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों? नरेंद्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोयम दर्जा का लेबल हट रहा है। हिंसा एवं अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है। बड़ी संख्या में छोटे शहरों और गांवों की लड़कायां पंद-लिखकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभारही हैं। वे उन क्षेत्रों में जा रही हैं, जहां उनके जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। वे टैक्सी, बस, ट्रक से लेकर जेट तक चला-उड़ा रही हैं।

या नहीं, क्योंकि यह पोषक तत्वों की खाद्य सुरक्षा, घटनाओं के लिए तैयार रासायनिक पदार्थों से दूषित भोजन खाने ऊपर में कमी, पोषण गुणवत्ता की प्रबंधन नीति का अभाव, खाद्यान्तर्गत हड्डों के प्रदर्शन करने के लिए अपने दायराएँ अपने बीचे एवं दायराएँ अपने बीचे

खाद्य सुरक्षा की स्थि

सभा लागा कि पास हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के उपलब्ध भाँति एवं आर्थिक पहुंच तथा उपलब्ध होती है, ताकि एक सक्रिय एवं स्वतंत्र जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताएँ एवं खाद्य वरीयताएँ की पूर्ति हो सके। खाद्य सुरक्षा इस बढ़का बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक है कि लोग सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकते

जो लोगों का गुरा करन के लिए अप्रत्याख्यात
खाद्य पदार्थों तक उनकी पहुँच निश्चय
करता है। खराक खाने से पनपने व
खतरे को पहचानने और सामग्रजे
लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सं-
राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन
सहयोग से इस वर्ष 7 जून को नए
के साथ खाद्य सुरक्षा दिवस मना
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024
विषय था- हाखाद्य सुरक्षा : अप्रत्याख्यात
के लिए तैयारी करें हँ इस वर्ष का

रहने के नियमों का खात्याकांक्षा बढ़ते हैं, जाहे वे कितनी भी हल्की या गहरी चुंबनों नहीं हों। खाद्य सुकृति मनने के लक्ष्य हैं : खाद्य सुकृति, मसाला स्वास्थ्य, अधिक समृद्धि, कृषि बाय पहुंच, सतत विकास में योगदान व खाद्य जनित जोखिमों का पता लगाएवं रोकने तथा प्रबंधित करने में हेतु ध्यान अकार्यकृत करने और कानूनों को प्रेरित करने हेतु। एक अनुमान अनुसार हार साल बायरस, बैक्टीरी

लान लगाने 600 मिलियन लान बढ़ाया गया है। इनमें ज्यादातर औरतें भव्य वर्षा हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एक हर साल 125000 मौतें होती हैं। सभी राष्ट्रों में खाड़ी सुरक्षा में चुनौतियाँ चिह्नित की जा रही हैं जो कि : जलवायु परिवर्तन, नदी तापमान, मौसम की परिवर्तनशीलता आक्रमणकारी फसल कीट और लगानी चरम मौसमी घटनाओं का खेती विकास पर हानिकारक प्रभाव आदि। इ

निरापेक्ष जारी करका उपचार न होता। असुरों की वजह से भारतवर्ष में असुरक्षा और गरीबी दोनों के स्तर कमी आई है। साथ में जनसंख्या बढ़िये के दबाव को भी सहन किया परन्तु अभी भी खाद्य सुरक्षा को रखने में बहुत सी चुनौतियां हैं। बढ़ते भूमि क्षरण, मृदा उत्तरवाहिनी, जल जगमव, जलवायु परिवर्तन और वैशिक आपूर्ति श्रृखला में व्यवहार (रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण),

हा
यदि
में
है।
एग
नमें
की
न,
अन
द्य

